



नव भारत



पंजाब की ऐतिहासिक औद्योगिक और कारोबार नीति 2026

औद्योगिक विकास और प्रगति की ओर अहम कदम
देश भर में सबसे बेहतरीन

एक व्यापक और
24 सेक्टरल नीतियों की एक
साथ घोषणा

निवेशक अपना
पैकेज डिज़ाइन करने के लिए
20 इंसेंटिव्स तक का चयन कर
सकते हैं

रोज़गार
सृजन सब्सिडी के लिए पात्रता
घटाकर ₹25 करोड़ और 50 श्रमिकों
तक की

पहली बार
कैपिटल सब्सिडी की शुरुआत

आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाएँ
इंसेंटिव्स के लिए पात्र

ज़मीन, श्रमिकों के लिए आवास, आर. एंड डी.
सुविधाएँ, ईटीपी/एसटीपी/ज़ेडएलडी
आदि को एफसीआई की गणना
में शामिल किया

महिलाओं, एससी/एसटी, पीडब्ल्यूडी,
आईटी/आईटीईएस और जीसीसी
के लिए उच्च रोज़गार सृजन सब्सिडी दरें

निवेशक इंसेंटिव्स के रूप में 100%
तक एफसीआई का लाभ प्राप्त कर सकते हैं

9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और सीमा तथा
तटीय क्षेत्रों के लिए 25% अधिक
इंसेंटिव

मोहाली में सरकारी स्टार्टअप हब
स्थापित किया जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए
सीड ग्रांट्स में वृद्धि की

आईटी/आईटीईएस/जीसीसी, ईवीज़,
ईएसडीएम, सेमीकंडक्टर, फ़िल्म निर्माण
और पर्यटन के लिए नई समर्पित नीतियों
की शुरुआत

- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए माल ढुलाई और मार्केटिंग सब्सिडी सहायता
- मेगा परियोजनाओं के लिए कस्टमाइज़्ड पैकेज कमेटी

- निवेशकों के लिए इंसेंटिव अवधि को 15 वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प
- बिजली, श्रम और भवन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार

हमारे साथ जुड़ें:

प्रोग्रेसिव पंजाब
इन्वेस्टर्स समिट 2026

13-15 मार्च, 2026

प्लाक्षा यूनिवर्सिटी, मोहाली

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

स. भगवंत सिंह मान
मुख्यमंत्री, पंजाब

